जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 17 संख्याः 271 प्रभात जालोर, शनिवार 7 जनवरी, 2023 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सफेद रंग का एक स्नोई आउल (उल्लू की एक प्रजाति), जो मूलतः आर्कटिक में मिलता है, 100 साल में पहली बार सदर्न कैलिफोर्निया में दिखा है। पूरे राज्य से बर्ड वॉचर्स इसकी झलक देखने आ रहे हैं। विश्व में इस प्रजाति के मात्र 30 हजार पक्षी ही बचे हैं। पिछले एक हफ्ते में कई बार यह पक्षी एक छत से दूसरी छत पर फुदकता नज़र आया। यह उल्लू 2000 मील दूर दक्षिण में कैसे आ गया, इसे लेकर रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मत है कि या तो यह किसी जहाज में बैठकर आया है या संरक्षण केन्द्र से भागा हुआ है। स्नोई आउल आर्कटिक टुंड्रा में मिलते हैं। लेकिन सफेद -काले रंग के ये पक्षी कई बार कैनेडा के दक्षिण तक प्रवास पर जाते हैं और आमतौर पर रेतीले समुद्र तटों पर ही पड़ाव डालते हैं। सदर्न कैलिफोर्निया तक तो शायद ही कभी आते हैं। स्नोई आउल सबसे बड़े नॉर्थ अमेरिकन आउल हैं। अपना अधिकांश समय ये आर्कटिक में गुज़ारते हैं और सर्दियाँ कैनेडा व अलास्का में। यह भी देखा गया कि कुछ स्नोई आउल वर्ष भर अपने ब्रीडिंग ग्राउण्ड में रहे। सैंटा एना रिवर वाइल्डलाइफ के साथ काम करने वाले रॉब यंग ने कहा, ''मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस पक्षी को देख पाया।'' कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि, यह वही स्नोई आउल है, जो कुछ सप्ताह पहले लॉस एंजलिस काउन्टी में दिखा था। एक शोधकर्ता, स्कॉट वाइनडैनसॉल ने कहा कि, स्नोई आउल विश्व के उस भाग में रहते हैं जहां इंसान का अस्तित्व ना के बराबर है और जहां पेड़ पौधों का नाम निशान नहीं होता। स्कॉट एक नॉन प्रॉफिट प्रौजैक्ट, स्नोस्टॉर्म के लिए काम करते हैं, जो स्नोई आउल का मूवमैंट ट्रैक करता है। स्कॉट का कहना है कि, कुछ स्नोई आउल हर साल सर्दी में आर्कटिक से दक्षिण की ओर जाते हैं पर यह संख्या हमेशा कम ज्यादा होती रहती है। उन्होंने कहा कि, स्नोई आउल का प्रिय भोजन लैमिंग्स (एक तरह का चूहा) हैं, जिनकी आबादी हर तीन से 5 साल में बढ़ जाती है। जब लैमिंग्स की संख्या बढ़ती है तो स्नोई आउल के ज्यादा चूजे जिंदा रहते हैं। इन वर्षों को ''इरप्शन'' वर्ष कहते हैं। इन ''इरप्शन'' वर्षों में ज्यादा पक्षी माइग्रेट करते हैं। अधिकांशतः सर्दियों में स्नोई आउल ग्रेट लेक्स या केप कॉड क्षेत्र से आगे नहीं जाते, पर ''इरप्शन'' वर्षों में वो आगे तक जा सकते हैं।

कर्नाटक में चला पर तमिलनाडू में नहीं चल पा रहा भाजपा का हिन्दुत्व का नारा

कई बार भाजपा ने हिन्दुओं के मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने का मामला उठाया, पर मुद्दा भावनात्मक जड़ें नहीं पकड़ पा रहा तमिलनाडू में

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। भाजपा का हिन्दुत्व का मुद्दा, जो कर्नाटक में अपना प्रभाव दिखा रहा है, पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में चारों खाने चित दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में, धार्मिक मुद्दों को जोर-शोर से उठाने की भाजपा की बार-बार की जा रही कोशिशें लोगों की भावनाओं को उभारने में असफल रही हैं। ज्ञातव्य है कि भाजपा की इस प्रकार की कोशिशें देश में लगभग हर स्थान पर उसे राजनैतिक लाभ देती आ रही हैं।

यही कारण है कि द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने भाजपा की इस माँग की अनदेखी कर दी है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिये जायें। अगर भाजपा का विश्वास किया जाये तो सरकार को मंदिरों पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह सरकार से अक्सर सवाल करती रहती है कि सरकार अन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों के मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार का नियंत्रण सचमुच रखती है। साफ बात यह है कि भाजपा चाहती है कि इस मुद्दे पर हिन्दू समुदाय को लामबंद एवं सक्रिय किया जाये।

- तमिलनाडू में 44,000 मंदिर हैं, जिन पर हिन्दू रिलिजस चैरिटेबिल एन्डाओमैंट एक्ट 1959, के मार्फत राज्य सरकार का नियंत्रण है।
- भाजपा बार-बार सवाल उठाती है कि, सरकारी नियंत्रण की यह विशेष व्यवस्था क्या अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी लागू है।
- डी.एम.के. सरकार, मु.मंत्री स्टालिन के मार्फत यह तर्क देती है कि, वह हिन्दू धर्म के खिलाफ नहीं है, पर मंदिरों के धन व सम्पदा का दुरूपयोग व अव्यवस्था व धर्मान्तरण को रोकने के लिये मंदिरों को अपने नियंत्रण में लिया है।
- तमिलनाडू की जनता सरकार व धर्म के मामले में भाजपा से ज्यादा द्रविड़ पार्टियों पर विश्वास करती है।
- यहां तक कि, भाजपा की सहयोगी पार्टी अन्नाद्रमुक भी मंदिरों के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है तथा भाजपा के समर्थन में नहीं खड़ी है।
- यह भांपते हुए डी.एम.के. का सार्वजनिक स्टैण्ड है, वह मंदिरों को ऐसे धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, जहां जाति, धर्म आदि के नाम पर भेदभाव न हो।

लेकिन, अन्य राज्यों से अलग हट कर, यह मुद्दा तमिलनाडु की आम जनता की कल्पना को अपनी गिरफ्त में लेने में असफल रहा है। जहाँ तक तमिलनाडु के स्थानीय शासन का प्रश्न है, यहाँ की जनता द्रविड़ पार्टियों पर भरोसा करती है तथा राष्ट्रीय दलों के दावों को सिरे से खारिज़ कर देती है। भाजपा की नज़रें 39 लोकसभा सीटों की बहुत बड़ी संख्या पर तथा तमिलनाडु की सत्ता पर लगी हैं लेकिन अभी तक तो भाजपा को तमिलनाडु की जनता अपनी सोच पर अडिग ही दिखाई दे रही है। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु की राजनीति को गंभीरता से लेने के लिये ही, भाजपा ने अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन किया है।

लेकिन जहाँ तक मंदिरों और उन पर सरकार के नियंत्रण का प्रश्न है, केवल भाजपा ही इस बिन्दु पर शोर-गुल करती तथा विरोध प्रदर्शन करती नज़र आ रही है, उसकी गठबंधन पार्टनर अन्नाद्रमुक के इस मुद्दे पर खामोश है तथा इससे सुरक्षित दूरी बनाये हुये है। इस स्थिति को देखते हुये, द्रमुक सरकार ने भाजपा की माँग को सरसरी तौर पर खारिज़ कर दिया है तथा वह भाजपा को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धीरे-धीरे सुधर रही है सोनिया की तबियत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, पर गंगाराम हॉस्पीटल, जहां बुधवार को उन्हें सांस में तकलीफ की वजह से भर्ती करवाया गया था, के डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

- पर, सर गंगाराम अस्पताल, जहां उन्हें श्वसन संक्रमण होने पर भर्ती करवाया गया था, के चिकित्सकों का कहना है कि, सोनिया की हालत स्थिर है।

सोनिया के साथ अस्पताल में उनकी बेटी प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका ने कहा कि उनकी मां को श्वसन संक्रमण हुआ है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर अपनी मां से मिलने आए हैं।

क्या नेपाल आतंकवादियों के भारत में अतिक्रमण का नया केन्द्र बनेगा?

पाकिस्तान से आतंकवादियों के अतिक्रमण को गति मिली, जब अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति गड़बड़ होने के बाद उसे ''ग्रे लिस्ट'' (संदिग्ध देशों की सूची) में डाला था

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। भारत-पाकिस्तान सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल (एल.ओ.सी.) से ही जैसे सीमापार आतंकवाद पर्याप्त नहीं था, अब संभावना है कि नेपाल को ऐसे देशों की ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है, जिनमें मनी लॉंड्रिंग और टैरर फायनैंसिंग का मुकाबला करने में रणनीतियां बनाने की कमी है। भारत को सावचेत रहना होगा क्योंकि ऐसी स्थिति नेपाल को अपने यहां आतंकवादियों को पनाह देने का दूसरा स्रोत हो सकती है।

हालांकि नेपाल ने मनी लॉंड्रिंग और टैरर फायनैंसिंग का मुकाबला करने के लिए कानूनों में संशोधन करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके कानूनों और उनके प्रवर्तन में ऐसी कमियां हैं जिसका सरकार को समाधान करना है।

फायनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ.) एक अन्तर्राष्ट्रीय नीति निर्माण इकाई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों की स्थापना करना, नीतियां बनाकर आगे बढ़ाना और मनी लॉंड्रिंग और आतंकवाद के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एफ.ए.टी.एफ. की विशेषज्ञों की टीम नेपाल के दौरे पर है तथा फरवरी में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
- रिपोर्ट का मुद्दा होता है, उस देश में ''मनी लॉण्डरिंग'' के मामलों में कितने कानून हैं तथा उन पर कितनी सख्ती से कार्यवाही होती है।
- टीम साथ ही यह भी देखती है कि, उस देश (नेपाल) की आतंकवाद को की जाने वाली फायनैंसिंग रोकने की कितनी क्षमता है और वह देश आतंकवादी गतिविधि फाइनैंसिंग का ''हब'' तो नहीं बन रहा।
- काठमांडू टाइम्स के एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार, नेपाल को ''ग्रे लिस्ट'' में शामिल करने की काफी संभावना है, क्योंकि उक्त पत्रकार के अनुसार मनी लॉण्डरिंग कानूनों में कई खामियाँ हैं तथा अनुपालना भी लचर है।

44 हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की 104 लम्बित सिफारिशों में 44 हाई कोर्ट जजों के नामों को इस सप्ताहांत तक मंजूरी देकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा।

- केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि, कोलीजियम ने जिन 104 नामों की सिफारिश की है, उनमें से 44 नामों को इसी सप्ताह केन्द्र सरकार क्लियरैंस दे देगी।

यह आश्वासन एटॉर्नी जनरल आर. वैंकटरमानी ने न्यायिक नियुक्तियों की समय सीमा का समर्थन करते हुए दिया। उन्होंने जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव कम करने के संकेत दिए। उन्होंने जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस. ओका की बैंच के समक्ष कहा कि सरकार सर्वोच्च

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस साल के अंत तक कुछ ''हैरिटेज ट्रेन'' हाइड्रोजन से चलने लगेंगी

छोटी लाइन की गाड़ियां हिमालय के पर्वतीय इलाकों में चल रही हैं तथा हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से ये रेल गाड़ियां पूर्णतया ''ग्रीन'' हो जायेंगी, क्योंकि प्रदूषण के रूप में केवल पानी ही निकलेगा, इन रेलगाड़ियों से

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। अश्विनी वैष्णव ने नैरो गेज रूट्स पर संचालित हैरीटेज ट्रेन्स में से किसी एक को वर्ष 2023 के अंत तक देश की पहली ''हाइड्रोजन ट्रेन'' बनाने की योजनाओं की घोषणा की है। जर्मनी ने पिछले वर्ष जुलाई माह से ही एक पैसेन्जर रूट पर एक प्रोटोटाइप हाइड्रोजन चालित ट्रेन शुरु की है जिसकी अधिकतम स्पीड 160 किमी. प्रति घंटा है। यद्यपि यह तकनीकी फिलहाल ओपन मार्केट के बजाए कारखानों में ही उपलब्ध है, इसलिए दिसम्बर 2023 की अंतिम समय सीमा मुश्किल प्रतीत होती है।

इस स्थिति में संबंधित एक अन्य मुद्दा यह है कि जर्मनी या यूरोपीय देशों के विपरीत भारतीय रेलवे की 70 प्रतिशत ईंधन जरुरतें अब भी कोयला, तेल व पैट्रोलियम जैसे फासिल फ्यूल्स से पूरी होती हैं। भारत के मामले में इन ट्रेनों का संचालित करने वाले हाइड्रोजन सिलैण्डर्स को चार्ज करने के लिए फिर भी फॉसिल फ्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन से कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स पर पर्यावरणीय प्रदूषण जारी रहेगा। इसलिए ''ग्रीन टैक्नॉलजी'' का सूत्रपात करने के रेलवे के दावे अनुपयुक्त हैं।

फ्रांस की ट्रांसपोर्टेशन की दिग्गज कंपनी ''ऑस्तम'' वर्ष 2016 में दुनिया की पहली कार्बन उत्सर्जन रहित क्षेत्रीय ट्रेन ''कोरोदिया आईलिन्त'' की शुरुआत की। इस ट्रेन का अब जर्मनी के एक पैसेन्जर रुट संचालन करने की कोशिश की जा रही है। इस देश ने ब्रेमेर्बेदे में दुनिया का पहला हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन भी बनाया है। फ्यूल सैल्स और हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले उपकरण की खोज कर रहे हैं। भारत की योजना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- छोटी लाइन की प्रमुख हैरिटेज रेलगाड़ियां हैंः दार्जिलिंग हिमालयन रेल, नीलगिरी माउन्टेन रेल, कालका शिमला रेलवे, माथेरन हिल रेलवे, कांगड़ा वैली रेल, बिलिमोरिया वागाई रेल तथा मारवाड़-देवगढ़-मदरिया रेल।

क्या मोदी ने अपनी पत्नी को नज़रबंद किया था?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदा बेन को घर में ही नज़रबंद कर दिया था ताकि वे अहमदाबाद में उनकी मां हीरा बेन के अंतिम संस्कार में

- एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्र.मंत्री मोदी की पत्नी जसोदा बेन अपनी सास हीरा बेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाना चाहती थीं, पर उनके घर को पुलिस ने घेर लिया और बाहर नहीं निकलने दिया।

शामिल ना हो पाएं। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट से मिली है।

अपनी सास हीरा बेन की मृत्यु से दुखी जसोदा बेन अपने भाईयों के साथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जाने को तैयार थी कि तभी उनके घर को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत जोड़ो यात्रा को वैस्टर्न यू.पी. में भारी समर्थन मिला

जम्मू-कश्मीर के भी कई वरिष्ठ नेता, जो गुलाम नबी की पार्टी में शामिल हो गये थे, पुनः कांग्रेस में लौटे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। इस समय जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा। जहाँ इसे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जन-समर्थन मिला है, वहीं जम्मू-कश्मीर के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचन्द भी शामिल हैं, आज सुबह कांग्रेस में वापस आ गये हैं। ज्ञातव्य है कि इन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ पार्टी छोड़ दी थी।

हरियाणा में प्रवेश करने पर, भारी भीड़ ने यात्रा का स्वागत किया तथा पानीपत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।

रैली को संबोधित करते हुये, रोज़गार के मोर्चे पर केन्द्र सरकार की असफलता को लेकर खड़गे ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश का युवा वर्ग पिछले 4-5 साल से बेरोज़गारी की सबसे बुरी स्थिति का सामना कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह 2 करोड़ रोज़गार सृजित करने के चुनावी वादे निरन्तर किये जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के वादे कभी पूरे नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में, यात्रा प्राथमिक रूप से उन क्षेत्रों से गुजरी, जो राष्ट्रीय लोक दल के गढ़ हैं। आर.एल.डी. के नेताओं ने इस मिशन का स्वागत किया तथा पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के विशेष निर्देशों पर, उन लोगों ने यात्रा में सहभागिता की। ज्ञातव्य है कि जयंत चौधरी इस समय विदेश में हैं। यात्रा में किसान नेताओं तथा सामान्य किसानों की सहभागिता रही। शामली में हुई सार्वजनिक सभा में भारी भीड़ थी। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आर.एल.डी. और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था।

इससे पूर्व, जम्मू कश्मीर के नेताओं का ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में स्वागत किया गया। ताराचन्द के अलावा कांग्रेस में वापस आने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में शामिल थे- पूर्व मंत्री पीरज़ादा मोहम्मद सईद, मनोहर लाल तथा बलवान सिंह।

गुलाम नबी आज़ाद के प्रति वफादार माने जाने वाले ये सभी नेता कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी (डी.ए.पी.) में शामिल हो गये थे। लेकिन आज़ाद ने ''पार्टी-विरोधी गतिविधियों'' को लेकर पिछले महीने ताराचन्द को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

ताराचन्द, मनोहर लाल तथा बलवान सिंह कांग्रेस के ऐसे पहले नेताओं में से थे, जो उस समय आज़ाद के पीछे आकर खड़े हो गये, जब आज़ाद ने पाँच दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद पिछले वर्ष अगस्त में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

किन्तु आज़ाद ने अपनी पार्टी का नाम चुनाव आयोग में पंजीकृत कराया ही था कि उन्होंने ताराचन्द, बलवान सिंह तथा पूर्व मंत्री डॉ. मनोहर लाल शर्मा को पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोपों को लेकर डी.ए.पी. से निष्कासित कर दिया था।

ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल, ए.आई.सी.सी. महासचिव जयराम रमेश तथा राज्य की ए.आई.सी.सी. प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में ये तीनों ही नेता कांग्रेस में शामिल हो गये।

घर-वापसी पर उनका स्वागत करते हुये, वेणुगोपाल ने कहा कि यात्रा (के जम्मू-कश्मीर पहुँचने) से पहले ही, पार्टी के लिये प्रसन्नता का अवसर है कि जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के ये दिग्गज नेता, जो कुछ गलतफहमियों के कारण हमें छोड़ गये थे, घर वापस आ गये हैं।'' उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इन नेताओं ने पार्टी से दो माह की छुट्टी ली थी। उन्होंने कहा, ''अवकाश समाप्त हो गया और ये लोग वापस आ गये हैं।''

ताराचन्द, मनोहरलाल तथा बलवान सिंह के अलावा, कांग्रेस में लौटने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में शामिल हैं- पूर्व पी.सी.सी. अध्यक्ष तथा तीन बार मंत्री रहे पीरज़ादा मोहम्मद सईद, मो. मुजफ्फर पर्रे, महेन्द्र भारद्वाज, भूषण डोगरा, विनोद शर्मा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इनमें प्रमुख थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद, पूर्व मंत्री पीरज़ादा मोहम्मद सईद, डॉ. मनोहर लाल व बलवान सिंह।
- इन नेताओं का महासचिव वेणुगोपाल ने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में स्वागत किया और कहा, ये नेता गण दो महीने की छुट्टी पर गये थे और अब छुट्टी खत्म होने पर वापस लौट आए।
- वैस्टर्न यू.पी. में राष्ट्रीय लोक दल के नेता व कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो विदेश में हैं, के स्पष्ट आदेशों की अनुपालना में भारत जोड़ो यात्रा में जोश व उत्साह से भाग लिया।

सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। नीति आयोग ने इस बात से इंकार किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण

- नीति आयोग ने इस बात से इंकार किया कि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव जारी किया गया है।

के प्रस्ताव से संबंधित कोई भी दस्तावेज जारी किया गया है।

मीडिया में सर्कुलेट हो रहे एक फर्जी मैसेज का नीति आयोग ने खंडन किया।

उक्त संदेश में उन बैंकों की लिस्ट हैं, जिनका नीति आयोग निजीकरण करना चाहता हैं।

नीति आयोग ने कहा, ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है।